

भारत में एसडि अटैक पर कानून

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो, भारतीय दंड संहता (IPC), वषऱ अधनलयऱ, 1919 ।

मेन्स के लयः

भारत में एसडऱ अटैक, एसडऱ अटैक संबंघी कानून, एसडऱ बकऱरी के नलयऱन पर कानून, एसडऱ अटैक पीडऱतऱं के लयऱ मुआवऱा और देखभाल

चरुा में कऱं?

हाल ही में दलऱली में तीन लडऱकूं दऱारा एक युवती पर एसडऱ अटैक कयऱ गयऱ । इस घटना ने एसडऱ अटैक के जघन्य अपराध और संकषऱरक पदऱरुथूं की आसान उपलबधता को केंद्रीय वषऱय बना दयऱ है ।

भारत में एसडऱ अटैक:

- **राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के आँकडूं के अनुसार, वरुष 2019 में 150, वरुष 2020 में 105 और वरुष 2021 में 102 ऐसे मामले दर्ज कयऱ गए थे ।
- पश्चमऱ बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले अधकऱ संख्यऱ में दर्ज कयऱ गए हैं, जो आमतौर पर साल-दर-साल देश के सभी मामलों का लगभग 50% होता है ।
- वरुष 2019 में एसडऱ अटैक की चऱरुजशीट दर 83% और सऱा दर 54% थी ।
- वरुष 2020 में इस प्रकार के मामले क्रमशः 86% और 72% थे तथा वरुष 2021 में क्रमशः 89% और 20% दर्ज कयऱ गए थे ।
- वरुष 2015 में गृह मंत्रऱलय ने सभी राज्यूं को अभयऱोजन में तेऱी लाकर एसडऱ हमलों के मामलों में त्वरतऱ न्यऱय सुनशऱचतऱ करने के लयऱ एक परऱमरुश जऱरी कयऱ थऱ ।

भारत में एसडऱ अटैक पर कानून:

- **भारतीय दंड संहता:** वरुष 2013 तक एसडऱ अटैक को अलग अपराध के रूप में नहीं मानऱ जऱता थऱ । हालाँकऱ **भारतीय दंड संहता (IPC)** में कयऱ गए संशोधनों के बाद एसडऱ अटैक को भारतीय दंड संहता (IPC) की एक अलग धऱरा (326A) के अंतरगत रखा गयऱ तथा 10 वरुष के न्यूनतम कारऱवास के साथ दंडनीय बनायऱ गयऱ थऱ, जो जुरमाने सहतऱ आजीवन कारऱवास के रूप में बढऱयऱ जऱ सकता है ।
- **उपचार से इनकार:** कानून में पुलसऱ अधकऱरयऱं दऱारा पीडऱतऱं की प्रऱथमकऱी दर्ज करने यऱ उपचार से इनकार करने पर सऱा का भी प्रऱवधान है ।
 - उपचार से इनकार (सार्वजनकऱ और नजीी दोनों अस्पतऱलों दऱारा) करने पर एक वरुष तक की कैद हो सकती है और पुलसऱ अधकऱरी दऱारा कऱतव्य की अवहेलना करने पर दो वरुष तक की कैद हो सकती है ।

एसडऱ बकऱरी के नलयऱन पर कानून:

- **वषऱ अधनलयऱ, 1919:** वरुष 2013 में सर्वोच्च न्यऱयालय ने एसडऱ अटैक का संजुऱान लयऱ और एसडऱ पदऱरुथूं की बकऱरी के नलयऱन पर एक आदेश पऱरतऱ कयऱ ।
 - आदेश के आधार पर गृह मंत्रऱलय ने सभी राज्यूं को एक सलाह जऱरी की कऱकैसे एसडऱ की बकऱरी को वनलयऱतऱ कयऱ जऱए और वषऱ अधनलयऱ, 1919 के तहत **मॉडल वषऱ कबुऱा और बकऱरी नलयऱ, 2013 (Model Poisons Possession and Sale Rules, 2013)** तैयऱर कयऱ जऱए ।
 - परणऱामस्वरूप राज्यूं को मॉडल नलयऱं के आधार पर अपने स्वयं के नलयऱ बनऱने के लयऱ कऱहऱ गयऱ कऱकऱं कऱमला राज्यूं के अधकऱर कषेतर में आतऱ थऱ ।

- **डेटा का रखरखाव:** एसडि की ओवर-द-काउंटर बकिरी (बना किसी वैध नुस्खे के) की अनुमति नहीं थी, जब तक कविकिरेता एसडि की बकिरी को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक/रजिस्टर नहीं रखता।
 - इस लॉगबुक में एसडि बेचने वाले व्यक्तिका विवरण, बेची गई मात्रा, व्यक्तिका पता और एसडि खरीदने का कारण भी शामिल होना था।
- **आयु प्रतिबंध और दस्तावेजीकरण:** बकिरी केवल सरकार द्वारा जारी पते वाली एक फोटो पहचान पत्र की प्रस्तुति पर की जानी है। खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
- **एसडि स्टॉक की ज़बती: कविकिरेता को 15 दिनों के भीतर और एसडि के अधोषति स्टॉक के मामले में संबंधित उप-वभागीय मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate- SDM) के साथ एसडि के सभी स्टॉक की घोषणा करनी होगी।** SDM स्टॉक को ज़बत कर सकता है और किसी भी दशा-नरिदेश के उल्लंघन के लिये **उपयुक्त रूप से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।**
- **रिकॉर्ड-कीपिंग:** नयियों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, सरकारी वभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वभागों, जिन्हें एसडि रखने एवं स्टोर करने की आवश्यकता होती है, को एसडि के उपयोग का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा संबंधित SDM के साथ इसे दर्ज करना होगा।
- **जवाबदेही:** नयियों के अनुसार, एक व्यक्तिको अपने परसिर में एसडि और सुरक्षति रखने के लिये जवाबदेह बनाया जाएगा। एसडि को इस व्यक्तिकी देखरेख में संग्रहीत कया जाएगा तथा प्रयोगशालाओं/भंडारण के स्थान को छोड़ने वाले छात्रों/कर्मयियों की अनविर्य जाँच होगी जहाँ एसडि का उपयोग कया जाता है।

एसडि-अटैक पीड़तियों हेतु मुआवज़ा और देखभाल:

- **मुआवज़ा:** एसडि अटैक पीड़तियों को संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासति प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनरवास लागत के रूप में कम-से-कम 3 लाख रुपए का मुआवज़ा दया जाता है।
- **नःशुल्क उपचार:** राज्यों से अपेक्षा की जाती है कवि ये यह सुनिश्चित करें क एसडि अटैक के पीड़तियों को सार्वजनिक या नजिी किसी भी अस्पताल में नःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। पीड़ति को दयि जाने वाले एक लाख रुपए के मुआवज़े में इलाज पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं कया जाना चाहयि।
- **बसितरों का आरक्षण:** एसडि अटैक के पीड़तियों को प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रया से गुज़रना पड़ता है और इसलिये एसडि अटैक के पीड़तियों के इलाज के लिये नजिी अस्पतालों में 1-2 बसितर आरक्षति कयि जा सकते हैं।
- **सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम:** राज्यों को भी पीड़तियों के लिये सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का वसितार करना चाहयि, जसिके लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को वशेष रूप से उनकी पुनरवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वतितपोषति कयि जा सकता है।

आगे की राह

- **कसिी को पीछे नहीं छोड़ने का वादा:** महिलाओं के खलिाफ हसिा समानता, वकिसा, शांति के साथ-साथ महिलाओं और लड़कयियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में बाधा बनी हुई है।
 - कुल मलिाकर **सतत वकिसा लक्षयों (SDG)** का 'कसिी को भी पीछे नहीं छोड़ने का वादा' महिलाओं और लड़कयियों के खलिाफ हसिा को समाप्त कयि बनिा पूरा नहीं कयि जा सकता है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** महिलाओं के खलिाफ अपराध को अकेले कानून की अदालत में हल नहीं कयि जा सकता है। इसके लयिसमग्र दृष्टिकोण और संपूर्ण पारसिथितिकी तंत्र को बदलने की आवश्यकता है।
- **भागीदारी:** कानून नरिमाताओं, पुलसि अधकारयियों, फोरेंसिक वभाग, अभयिोजकों, न्यायपालका, चकितिसा एवं स्वास्थय वभाग, गैर-सरकारी संगठनों तथा पुनरवास केंद्रों सहति सभी हतिधारकों को एक साथ मलिाकर काम करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. समय और स्थान के वरिद्ध भारत में महिलाओं के लयि नरितर चुनौतयि कया हैं? (मेन्स-2019)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस